25 JUL 2011

नव दुनियाँ, भोपाल

सभी राज्यों को दी मप्र की विकेन्द्रीकृत जिला योजना मॉडल अपनाने की सलाह

दिल्ली ने माना मप्र का लोहा!

वैभव श्रीधर भोपाल

अमूमन केंद्रीय योजनाओं के प्रदेश में क्रियान्वयन को लेकर मीनमेख निकालने वाले केंद्रीय योजना आयोग की बोलती इस बार बंद है। आयोग के दिग्गजों ने विशेषज्ञों से परीक्षण कराने के बाद मप्र की आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) आधारित विकेन्द्रीकृत जिला योजना का लोहा मान लिया है। इस पारदर्शी व्यवस्था में कोई किसी भी बैठक, किसी भी गांव और वार्ड के लोगों की प्राथमिकता, मौजूदा सुविधा, कमियां, बजट आवंटन और वहाँ चल रहे कामों की स्थिति ऑनलाइन देख सकता है। यही वजह है कि आयोग की सदस्य सचिव सुधा पिल्लै ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को खत लिखकर मध्यप्रदेश मॉडल अपनाने का मशविरा दिया है।

केंद्रीय योजना आयोग ने बीते साल यह व्यवस्था बनाई थी कि राज्य की योजनाओं को मंजूरी तभी दी जाएगी, जब वह विकेन्द्रीकृत जिला योजना बनाकर लाएंगे। इसके मद्देनजर प्रदेश के राज्य योजना आयोग ने एक कदम आगे बढ़कर वन महकमे के सूचना प्रौद्यागिकी विशेषज्ञों की मदद से ऐसा सॉफ्टवेयर बना डाला, जिससे सभी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो गईं। हालांकि, इसके लिए राज्य योजना आयोग को एक साल खूब मेहनत करनी पड़ी। उन्होने चार चक्रों में प्रशिक्षण देकर 54 हजार से ज्यादा गांवों और वार्डों में दल भेजकर चौपाल लगाई। समस्या और प्राथमिकताएं पूछीं। इसके हिसाब से गांव, तहसील और जिला की योजना बनाई। जिला योजनाओं को समाहित करते हुए राज्य की वार्षिक योजना का तानाबाना विभागों से अभिमत लेने के बाद बुना गया।

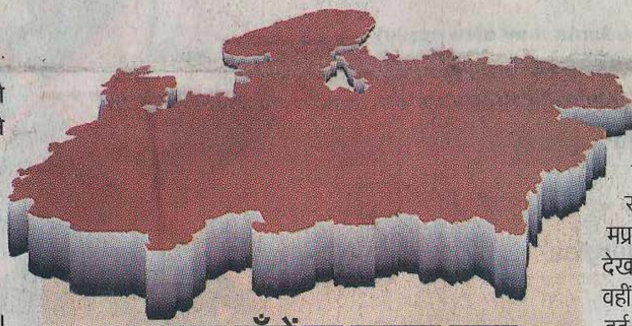

42 हजार गाँवों का मास्टर प्लान

इस पूरी प्रक्रिया का फायदा यह हुआ मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक 42 हजार गांवों का मास्टर प्लान तैयार हो गया। कुल 54 हजार गाँवों का मास्टर प्लान बनना है। इस मास्टर प्लान के जरिए अब वल्लभ भवन या विंध्याचल स्थित आयोग के कार्यालय में बैठकर बताया जा सकता है कि किस गांव में क्या समस्या है। इसे दूर करने में कितना वक्त और धन लगेगा। यही नहीं जब आगामी वर्ष की योजना बनाने के लिए प्रशिक्षित दल गांव या वार्डों में जाएंगे तो पहले बीते साल स्वीकृत हुए कामों का ब्यौरा एकत्र कर फीडबैक सीधे तहसील स्तर से ऑनलाइन भेजा जाएगा।

अहलूवालिया ने की थी पूछताछ

आयोग के सूत्रों का कहना है कि केन्द्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने दिल्ली में आयोग के कार्यालय में मप्र के प्रस्तुतिकरण के दौरान अधिकारियों से यह सवाल किया था कि यदि मैं अमेरिका के शिकागो में हूँ और मुझे मप्र के बैतूल जिले के किसी गांव का प्लान और स्वीकृत कामों को देखना है तो क्या मैं देख सकता हूँ? इस पर अधिकारियों ने उन्हे वहीं बैतूल के एक गाँव का ब्यौरा दिखा दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। आयोग ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अफसरों की मदद से विशेषज्ञों को इस मॉडल की तकनीक का परीक्षण करने में लगाया। उन्होंने रिपोर्ट दी कि यह फुलप्रूफ और पारदर्शी व्यवस्था है।

> “ केरल में 30 साल पहले प्लानिंग के लिए विकेन्द्रीकृत सिस्टम को अपनाया गया। लेकिन हमारा मॉडल उनसे भी एडवांस है। केन्द्रीय योजना आयोग इस मॉडल से न केवल प्रभावित है, बल्कि उसने सभी राज्यों को सलाह दी है कि योजना की इस पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाया जाए। यह हमारे लिए गौरव की बात है।
>
> **– मंगेश त्यागी, सलाहकार, राज्य योजना आयोग** ”